घाटे में पावर कंपनियां टाटा पावर के CEO अनिल सरदाना ने कहा, हाइड्रो पावर को दोबारा बढ़ावा देना शुरू करे सरकार

प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनियों के लिए मुश्किल दौर

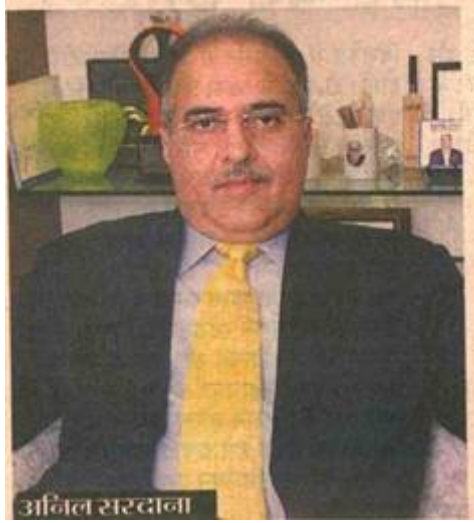
अनिल सरदाना

*देश के थर्मल पावर सेक्टर में रिकवरी धीमी है और हाइड्रो पावर कैपेसिटी में कमी से देश की एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान हो रहा है। टाटा पावर के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर **अनिल सरदाना** ने ईटी की **रचिता प्रसाद** और **आर श्रीराम** को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई पावर कंपनियां अपनी एसेट्स बेचना चाहती हैं क्योंकि उनकी इक्विटी प्रोजेक्ट्स में फंसी है। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश:*

हाइड्रो पावर सेक्टर में क्या हो रहा है? क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं?

देश में हाइड्रो पावर की कैपेसिटी घटी है। कुल एनर्जी में इसकी हिस्सेदारी 30 पर्सेंट से घटकर 17 पर्सेंट पर आ गई है और अगले वर्ष यह और गिरकर 15 पर्सेंट रह जाएगी। यूरोपियन देश रिन्यूएबल पावर का जेनरेशन घटने पर गैस-बेस्ड पावर का इस्तेमाल करते है, लेकिन भारत के पास गैस नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार हाइड्रो पावर को दोबारा बढ़ावा देना शुरू करे। कैपिटल की ऊंची कॉस्ट से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान होता है क्योंकि राज्य सस्ती बिजली चाहते हैं। अभी फोकस हाइड्रो पर नहीं रिन्यूएबल एनर्जी पर है।

घाटे में चल रही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की स्थिति सुधारने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आने के बाद स्थितियों में कितना सुधार हुआ है।

उदय एक अच्छी स्कीम है। यह डिस्कॉम के खाते साफ कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नुकसान दोबारा न बढ़ें। उदय से डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल पोजिशन में सुधार होगा, लेकिन डिस्कॉम्स को अपनी ओर से भी काम करना होगा। उन्हें बेहतर कमर्शियल मैनेजमेंट और फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है जिससे भविष्य में उनके नुकसान न बढ़ जाएं।

अभी उदय के दायरे से प्राइवेट डिस्कॉम्स बाहर हैं, लेकिन आपने बड़े रेगुलेटरी एसेट्स जमा किए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है?

उदय स्कीम के तहत रेगुलेटरी एसेट लिक्विडाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं किया जा रहा या इसके लिए कोशिश नहीं हो रही क्योंकि अभी फ्रेमवर्क काफी हद तक फिस्कल लॉस की ही बात कर रहा है।

क्या प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनियों के लिए अभी भी सीखने के दिन हैं?

पिछले 10 वर्षों में पावर सेक्टर में काफी इनवेस्टमेंट हुआ है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा योगदान है। बहुत से प्रोजेक्ट्स को दी गई माइंस कैंसल कर दी गई हैं। उनकी माइंस चली गई हैं और टैरिफ में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में वे कारोबार में कैसे बने रहेंगे और कर्ज चुकाएंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स के पास पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हैं क्योंकि राज्यों ने बिड नहीं मंगाई हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी इक्विटी लॉक्ड है और ऐसे में इक्विटी में बढ़ोतरी होना एक चुनौती है।

इस एनवायरमेंट में टाटा पावर की क्या स्ट्रैटेजी है?

हमने चार वर्टिकल्स की पहचान की है और अपने एग्जिक्यूटिव्स से मौकों की खोज करने को कहा है। हम उन मौकों पर फोकस करेंगे जहां हमें क्लीयरेंस मिलेंगी और रिस्क को कम कर रिटर्न हमारी सीमा से अधिक होगा।